हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर

वर्षः4 अंकः248 पृष्ठः08 मुल्यः1 रूपये | pathpravah.com | हरिद्वार, शुक्रवार, 12 सितंबर 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी

पथ प्रवाह, देहरादून

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देहरादून का दौरा किया और उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में बादल फटने, बारिश और भूस्खलन के कारण बाढ़ की स्थिति और नुकसान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा और नुकसान का आकलन करने के लिए देहरादून में एक आधिकारिक बैठक की। उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से राहत प्रदान करने और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करने जैसे उपाय शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के पुनर्निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत ÷विशेष परियोजना÷ के अंतर्गत उन पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके घर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।केंद्र सरकार ने पहले ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दलों को उत्तराखंड भेज दिया है, जो नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के उन परिवारों से मुलाकात की जो हाल ही में भूस्खलन और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सभी पीड़ित लोगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की और उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाढ़ और अन्य आपदाओं में मृतकों के निकटतम परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा कि हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता मिलेगी, जिससे उनकी दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस समय राज्यों को अग्रिम भुगतान सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत घोषित सहायता अंतरिम अवधि के लिए है। केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन की आगे समीक्षा करेगी। उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्य में योगदान देने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केन्द्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा जनता के प्रति अटूट आत्मीयता का जीवंत परिचायक

पथ प्रवाह, देहरादून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आई भीषण प्राकृतिक आपदा की स्थिति तथा राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा हेतु देहरादून पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया।

सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा प्रदेशवासियों के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का प्रतीक है। आपदा प्रभावित परिवारों के बीच उनकी उपस्थिति ने राहत एवं बचाव कार्यों को नई गति प्रदान की है, बल्कि लोगों में आशा और विश्वास का नया संचार भी किया है। उनका यह कदम केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति करुणा और उत्तराखंड की जनता के साथ अटूट आत्मीयता का जीवंत परिचायक है।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा, सांसद गढ़वाल अनिल बलूनी, सांसद नैनीताल अजय भट्ट, सांसद टिहरी माला राज्यलक्ष्मी शाह, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक', पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, हरिद्वार विधायक मदन कौशिक सहित अनेक वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं संकल्प से उत्तराखंड निश्चित रूप से इस संकट से उबरकर एक सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर अग्रसर होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाकी वर्दी को दी सौगात, एकीकृत भर्ती की व्यवस्था

योगेश शर्मा, पथ प्रवाह

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य के विभिन्न विभागों के वर्दीधारी उपनिरीक्षक एवं सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती में एकरूपता लाने के लिए बनाई गई एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू कर दी गई हैं। राज्य में विभिन्न विभागों के समूह 'ग' के वर्दीधारी उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया को विहित करने के उद्देश्य से 'उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025' और वर्दीधारी सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया को विहित करने हेतु 'उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025' बनाए जाने के संबंध में अधिसूचनाएं शासन के गुरूवार को जारी की गई। 'उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025' गृह विभाग के अधीन वेतन लेवल-7 में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/ अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (पी.ए.सी./ आई.आर.बी.), अग्नि शमन द्वितीय अधिकारी के पदों और उप कारापाल (वेतन लेवल-6) के साथ ही वेतन लेवल-5 में होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर, वन विभाग के वन दरोगा, आबकारी विभाग के आबकारी उप निरीक्षक तथा युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में लागू होगी। शासन द्वारा जारी 'उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025' के अंतर्गत गृह विभाग के आरक्षी पुलिस, आरक्षी पी.ए.सी., आरक्षी आई.आर.बी., अग्निशामक एवं बंदी रक्षक, वन विभाग के वन आरक्षी, आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही तथा सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालय/ विधान भवन रक्षक के वेतन लेवल-3 के पदों को शामिल किया गया है। राज्य के युवाओं के हितों व सुविधा का ध्यान रखते हुए विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षक एवं सिपाही के पदों पर एकीकृत भर्ती की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है।

एक नजर

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने दाखिलों की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ायी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय हरिद्वार में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिलों की तिथि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। पाठ्यक्रमों में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर छात्र-छात्राओं को एडमिशन दिया जाएगा।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलसचिव प्रो. विपुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए और कई पाठ्यक्रमों में खाली रह गई सीटों को लेकर दाखिलों की तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में बीए, एमए में हिंदी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, वेद, संस्कृत, योग, ज्योतिष, बीजे हिंदी पत्रकारिता और बीएससी, एमएससी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, माइक्रो बायोलॉजी, पर्यावरण और जंतु विज्ञान आदि पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहे हैं।

हरिद्वार में 12 को लगेगा विशाल रोजगार मेला, 23 कंपनियाँ देंगी युवाओं को रोजगार के अवसर

पथ प्रवाह, हरिद्वार। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, जिला सेवायोजन कार्यालय हरिद्वार और पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में 12 सितम्बर 2025 को विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोशनाबाद में प्रातः 10 बजे से शुरू होगा। इस रोजगार मेले में 23 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ भाग लेंगी, जिनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटो कॉर्प, विप्रो, आईटीसी लिमिटेड, किरबी बिल्डिंग सिस्टम, गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्रीज, सीएनएच इंडस्ट्रियल, पैनासोनिक जैसी बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं।

खास बातें

कुल पदः 1,016 से अधिक रिक्तियाँ
योग्यताः आईटीआई, डिप्लोमा, बी.फार्मा, बी.टेक, एम.एससी. आदि
आयु सीमाः 18 से 30 वर्ष (कंपनी के अनुसार भिन्न)
अधिकतम अवसरः सीएनएच इंडस्ट्रियल में 300 पद और डीसेट्स में 100 पद
महिंद्रा, हीरो, मकाइनो ऑटोमोटिव जैसी कंपनियों में भी युवाओं को दर्जनों अवसर मिलेंगे।

पंजीकरण

जिला सेवायोजन अधिकारी, हरिद्वार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार मेले में भाग लेने हेतु विज्ञप्ति में दिए गए त्तक्र कोड को स्कैन कर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

यह मेला युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, जिसमें उन्हें नामी कंपनियों में सीधे इंटरव्यू देकर नौकरी पाने का मौका मिलेगा।

आपदा की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तराखंड को संवेदनशील संबलः त्रिवेन्द्र

पथ प्रवाह, संवाददाता, देहरादून। आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भावुक हो उठे। उन्होंने प्रभावित जनों को भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार पूरी शक्ति व संसाधनों के साथ हर परिवार के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लिए ?1200 करोड़ की तात्कालिक सहायता की घोषणा की। साथ ही दिवंगतों के परिजनों को ?2 लाख, घायलों को ?50,000 की आर्थिक मदद, अनाथ बच्चों के लिए PM CARES for Children योजना का लाभ तथा क्षतिग्रस्त घरों, विद्यालयों, खेतों, बागवानी, होटल एवं अन्य बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण हेतु विशेष सहयोग का आश्वासन दिया। आवश्यकतानुसार नियमों में बदलाव करने की भी उन्होंने बात कही। इस अवसर पर हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री जी के इस स्नेह, संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प के लिए प्रदेशवासियों की ओर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह सहयोग पुनर्वास और पुनर्निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

नशे के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई, तीन तस्कर गिरफ्तार, चरस और गांजा बरामद

पथ प्रवाह, हरिद्वार

नगर कोतवाली पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग इलाकों से तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 120 ग्राम चरस, 107 ग्राम चरस और 1 किलो 10 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पुलिस टीम ने गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को अदालत में पेश कर दिया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए यह मुहिम लगातार जारी रहेगी।

आरोपी नंबर 1

-अभियुक्त ओमदत्त पुत्र जोगीराम निवासी-ग्राम अजीतपुर थाना कनखल हरिद्वार उम्र-53 वर्ष से 107.60 ग्राम) अवैध चरस बरामद हुई 2-जोगेंदर पुत्र धर्मपाल निवासी जियापोता ,थाना कनखल ,जिला हरिद्वार उम्र 38 वर्ष से 120 ग्राम) अवैध चरस बरामद होना हुई

3- अमन पासवान पुत्र संतोष पासवान निवासी रेलवे फाटक मारवाडी धर्मशाला के पीछे निर्मला छावनी थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस टीम-

1- रितेश शाह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर हरिद्वार
2-उ0नि0 अंशुल अग्रवाल
3-उ0नि0 चरण सिंह चौहान
4-उ0नि0 संजीत कण्डारी
5-का 326 नापु हरीश रतूडी
6-का831 नापु कमल मेहरा
7-का कां0 579 रमेश चौहान

नगर निगम हरिद्वार ने शुरू किया 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान

पथ प्रवाह, संवाददाता

हरिद्वार। नगर निगम हरिद्वार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती (2 अक्टूबर) तक चलने वाले ÷स्वच्छता ही सेवा÷ विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक रूप से संचालित होगा, लेकिन नगर निगम ने अग्रिम तैयारी के तौर पर 11 सितम्बर से ही सफाई कार्यों को गति दे दी है।

नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश पर हुआ आगाज़

नगर आयुक्त आईएएस नंदन कुमार के दिशा-निर्देशों पर वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में आज पूरे नगर निगम क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। निगम के अधिकारियों और सफाई निरीक्षकों ने प्रमुख स्थानों पर स्वयं नेतृत्व कर स्वच्छता कार्यों को सुनिश्चित किया।

प्रमुख क्षेत्रों में चला सफाई अभियान

गंगा घाटों और रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में मुख्य सफाई निरीक्षक अर्जुन सिंह ने नेतृत्व किया।

लालजीवाला और हरकी पैड़ी क्षेत्र में सफाई निरीक्षक धीरेंद्र सेमवाल ने मोर्चा संभाला। भोपतवाला क्षेत्र में मुख्य सफाई निरीक्षक मनोज कुमार और कनखल-बैरागी क्षेत्र में मुख्य सफाई निरीक्षक श्रीकांत ने अभियान को गति दी। ज्वालापुर क्षेत्र में मुख्य सफाई निरीक्षक विकास छाछर और अनुभवी निरीक्षक विकास चौधरी ने मिलकर अभियान को सफल बनाया। मायापुर और कांवड़ पटरी क्षेत्र में मुख्य सफाई निरीक्षक संजय शर्मा ने सफाई कार्य संपन्न करवाया।

2 अक्टूबर तक निरंतरता

नगर निगम ने योजना बनाई है कि आगामी 2 अक्टूबर तक इसी प्रकार सभी वार्डों और प्रमुख धार्मिक-सामाजिक स्थलों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान गंगा घाटों, मुख्य बाजारों, धार्मिक स्थलों और यात्री मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नागरिकों से अपील

नगर निगम ने शहरवासियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अभियान में सहयोग करें, कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें और शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी निभाएँ।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कॉलेज में बच्चों के साथ बैठकर चखा मध्यान्ह भोजन

पथ प्रवाह, धीरज शर्मा, हरिद्वार।

हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गुरुवार को राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर महदूद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और पठन-पाठन की गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने छात्र-छात्राओं की उपस्थिति की जानकारी ली और शिक्षकों को निर्देशित किया कि विद्यार्थियों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न रह जाए।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि शिक्षक-शिक्षिकाएं बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरी निष्ठा और मेहनत से पढ़ाई कराएं। कक्षाओं का निरीक्षण करते हुए उन्होंने छात्राओं से पाठ्यक्रम से जुड़े सवाल भी पूछे और कहा कि मेहनत और परिश्रम से ही सफलता हासिल की जा सकती है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बच्चों के बीच जमीन पर बैठकर मिड-डे मील का स्वाद भी चखा और इसकी गुणवत्ता परखा। उन्होंने प्रधानाचार्य और भोजन माता को निर्देश दिए कि भोजन की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।

कक्षा-कक्षों की पट्टियां न लगी होने पर जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही फर्नीचर की आवश्यकता और मरम्मत कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। कॉलेज परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने चारदीवारी निर्माण के लिए दो लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की। उन्होंने छात्र-छात्राओं के शौचालयों की साफ-सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि वर्तमान में कॉलेज में कुल 911 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनमें 398 छात्र और 513 छात्राएं शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी रती लाल शाह, प्रधान प्रतिनिधि पप्पू सिंह पाटिल सहित शिक्षक, कर्मचारी और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

अपर सचिव झरना कमठान ने महिला समूहों के उत्पादों का किया निरीक्षण

पथ प्रवाह, सिद्धार्थ त्रिपाठी, हरिद्वार।

उत्तराखंड सरकार में अपर सचिव ग्राम्य विकास एवं परियोजना निदेशक झरना कमठान ने गुरुवार को जनपद हरिद्वार में ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के तहत संचालित गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला सीएलएफ और स्वयं सहायता समूहों के उद्यमों की प्रगति, उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार संभावनाओं की समीक्षा की। सबसे पहले उन्होंने खानपुर विकासखंड स्थित सिंघाड़ा प्रोसेसिंग यूनिट का दौरा किया। यहां उत्पादन प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए उन्होंने आटे का उत्पादन शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। जिला परियोजना प्रबंधक संजय सक्सेना और सीएलएफ अध्यक्षा ने अवगत कराया कि सिंघाड़े का उत्पादन अक्टूबर से प्रारंभ होते ही नियमित आपूर्ति बहाल हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने रुड़की विकासखंड में हिलांस बेकरी यूनिट का निरीक्षण किया।

महिला समूहों द्वारा तैयार की जा रही सिंघाड़ा कुकीज़ व अन्य उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग की जानकारी लेकर उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। क्वालिटी टीम द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

अपर सचिव ने ब्लॉक कार्यालयों का औचक निरीक्षण भी किया, जहां सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे के निर्देशन में निर्माणाधीन लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया और कार्य समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान परियोजना निदेशक (डीआरडीए) कैलाश नाथ तिवारी, जिला परियोजना प्रबंधक संजय सक्सेना, बीडीओ-एबीडीओ, रीप एवं एनआरएलएम टीम, सीएलएफ प्रतिनिधि सहित कई अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

मेडिकल स्टोर की आड़ में नशे का कारोबार, नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार

पथ प्रवाह हरिद्वार। मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि को सफल बनाने के लिये व पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन लगाम को सफल बनाने के लिये एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वालों के विरुद्व प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली लक्सर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक मेडिकल संचालक को मेडिकल स्टोर की आड में नशीले कैप्सूलो की तस्करी करते पकड़ा। उसके पास से 60 अवैध नशीले कैप्सूल बरामद किये गए। अभियुक्त के विरूद्ध कोतवाली लक्सर पर एनडीपीएस

एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके अलावा लक्सर क्षेत्र के अन्य मेडिकल स्टोरों की भी जांच पडताल की गई। एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल के निर्देश पर कोतवाली लक्सर पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर मेडिकल स्टोरों को चैक किया। इस दौरान चैक किए गए 185 मेडिकल स्टोर्स में से कई में अनियमितता पाये जाने पर संचालकों को फटकार लगाते हुए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित अन्य दिशा निर्देश दिए गए। संचालकों को स्पष्ट शब्दों में चेताया गया कि नशीली दवाओं की अवैध बिक्री में संलिप्तता पायी गई तो कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। हिदायत दी गई कि मेडिकल स्टोर का संचालन उसी व्यक्ति द्वारा किया जाये जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है।

सीएमओ ने किया ब्लड बैंक का निरीक्षण, गंदगी देखकर भड़के

पथ प्रवाह हरिद्वार। जिला चिकित्सालय हरिद्वार में ब्लड बैंक का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर.के. सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक में आपूर्ति के लिए सभी ब्लड ग्रुप का ब्लड मौजूद रहे। सीएमओ ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य पखवाड़ा चलाया जाएगा। जिसमें 17 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भूपतवाला में स्वास्थ्य पखवाड़े के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक के बाहर गंदगी देख कर सीएमओ ने नाराजगी जाहिर की। सड़क पर शिविर का गंदा पानी बहते देख कहा कि इससे संक्रामक रोगों का खतरा हो सकता है, इसके लिए उन्होंने तत्काल ही इस समस्या को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। कर्मचारी नेता दिनेश लखेडा ने बताया कि समस्या के निदान के लिए नगर आयुक्त, विधायक मदन कौशिक और महापौर को संगठन की ओर से अवगत कराया गया है किंतु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

निरीक्षण के दौरान ब्लड बैंक प्रभारी डा. रविन्द्र चौहान, अमित कुमार, हरीश सेमवाल, रेना नय्यर, बेबी सैनी, दिनेश लखेडा, वणिक चौधरी इत्यादि उपस्थित रहे।

हॉकी में हरिद्वार ने देहरादून की टीम को 8–0 से हराकर जीती प्रतियोगिता

पथ प्रवाह हरिद्वार।

महाराणा प्रताप स्पोर्टस कालेज में आयोजित हुई राज्य स्तरीय विद्यालयी नेहरु हॉकी प्रतियोगिता में अण्डर-17 बालिका वर्ग में आवासीय बालिका हॉकी छात्रावास रोशनाबाद हरिद्वार की टीम ने

राजकीय इण्टर कालेज किशनपुर देहरादून की टीम को 8-0 से हराकर जीत दर्ज कर प्रतियोगिता अपने नाम की।

आवासीय बालिका हॉकी छात्रावास की टीम

अब दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय नेहरु हॉकी कप प्रतियोगिता में प्रतिमाग करेगी। जिला क्रीडा अधिकारी शबाली गरुंग द्वारा बालिकाओं एवं उनकी

कोच शिखा बिष्ट एवं दीपक चन्द जोशी को प्रतियोगिता जीतने कर खेल विभाग हरिद्वार का नाम रोशन करने पर बधाई दी।

इस अवसर पर प्रदीप कुमार उप क्रीडा अधिकारी, प्रजापति कुकरेती मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विक्रम सिंह कनिष्ठ सहायक और खेल प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

संपादकीय

भारत का लोकतंत्र- चुनौतियों के बावजूद मजबूत

पिछ्ले कुछ सालो में दक्षिण एशिया के देशों में भी जनता में गहरा असंतोष देखने को मिला है.. एक साल पहले श्रीलंका की जनता ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को देश छोड़ कर भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया था, और राष्ट्रपति भवन में क़ब्ज़ा जमा लिया था... यही बांग्लादेश में घटित हुआ, ऐसे ही पाकिस्तान में भी राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती रहती है... कुछ ही साल पहले म्यांमार में भी तख्तापलट कर दिया गया था... अभी बीते कुछ दिनों से नेपाल के युवाओं में गहरा असंतोष देखने को मिला, वहाँ की सरकार ने इन्टरनेट बंद करके युवाओं के आंदोलन को कुचलने की नाकाम कोशिशे की लेकिन युवाओं ने नेपाल की संसद भवन को ही फूंक दिया.. एक ही दिन में प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। नेपाल की सडकों में मंत्रियों को दौड़ा - दौड़ा कर पीटा.. सर्वदलीय बैठक में सामूहिक इस्तीफ़े देने के बाद देश को सुचारू रूप से चलाने की बात प्रधानमंत्री ने की.... सोचिए अगर नेपाल के प्रधानमंत्री इतने लोकतांत्रिक होते तो क्या नेपाल में ये स्थिति पैदा होती? बिल्कुल भी नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए ये कहावत फिट बैठती है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत का

पिछ्ले एक दशक से देश में भाजपा की सरकार है, जिसे कांग्रेस सहित देश की अन्य पार्टियां तानाशाही सरकार कहकर संबोधित करती हैं। जब भी किसी देश में जनता के द्वारा या सैन्य तख्तापलट होता है तो हमारे देश में एक बहस चलने लगती है कि हमारे देश में ऐसे तख्तापलट हो सकता है क्या.. जिसका सीधा सा जवाब है कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसा होना मुश्क़िल ही नहीं नामुमकिन है।

नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, जैसे देशों की तुलना भारत के लोकतंत्र के साथ नहीं हो सकती.... ये छोटे - छोटे मुल्क हैं, वहाँ ये सब हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ का क्षेत्रफल, जनसंख्या, समस्याएं भारत से बिल्कुल ही अलग हैं।

छोटे - छोटे देशों में व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन जितना आसान होता है भारत जैसे देश में इतना आसान नहीं होता। नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में भारत जैसे बहुराज्य नहीं है, हालांकि भारत में बहुत से राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, जिससे ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा देश सत्ता के हाथ में है दूसरा ये कि अन्य राज्य चुनावो में भाजपा हारती भी है, यही कारण है कि ऐसे मुद्दे हवा हो जाते हैं। भारत में सभी की अपनी अलग - अलग समस्याएं हैं। भारत में जहां अधिकांश लोगों को सरकार फ्री की रेवड़ी बांटकर पाल रही है, वहाँ जनता के पास सड़क पर उतरने का माद्दा नहीं है।

भारत एक विशाल विविधता वाला देश है, इसलिए यहां कुछ संगठन सत्ता पर कब्जा नहीं जमा सकते... दूसरी बात यहां मार्शल लॉ की भी गुंजाइश नहीं है, पढ़िए नेहरू जी ने 1952 में ही इन्तजाम कर दिया था। भारतीय लोकतंत्र की प्राचीर बहुत मजबूत है वो झोंकों से कमज़ोर नहीं होगी...एक बात और ये जो आपको संविधान बदलने वाली बात कही जाती है वो सिर्फ़ एक जुमला है, द्द1द्ब भी एक जुमला है....विपक्ष जहां जीत जाता है,वहीं द्द1द्ब का बहाना ध्वस्त हो जाता है..

सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ

नरेन्द्र भारती

सदियों पुरानी कहावत है कि सब कुछ लुटाकर होश में आये तो क्या हुआ।चंद गलतियों के कारण सब कुछ लुट चुका है। वर्तमान परिपेक्ष्य में यह कहावत सटीक बैठती है।16 जून 2025 से हिमाचल में बरसात का कहर मचा हुआ है। यह बरसात निर्बाध रुप से हो रही है। जुलाई,अगस्त दो महीने लगातार बरसात होती रही अब सितंबर माह में भी यह बरसात निरंतर जारी है अब पता नहीं कब तक यह सिलसिला जारी रहेगा यह भविष्य के गर्भ में है। बरसात के कहर ने जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।हजारों लोग मौत के मुहं में समा चुके हैं।बरसात के रौद्र रुप से हर तरफ तबाही का मंजर हुआ है। आज मानव अपनी करनी पर पछतावा कर रहा है लेकिन अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। लाचार व बेसहारा हो चुका मानव अब आंसू बहा रहा है।मानव अपनी गलतियों का नतीजा भुगत रहा है। काश पूर्व में यह गलतियां न की होती तो आज यह दुर्गति ना होती मगर माया में अंधा हो चुका इनसान बेहोश हो चुका था तब तक होश आया सब कुछ तबाह हो गया अब अपने किए कर्मौं का फल प्राप्त कर रहा है। किन्नौर से लेकर भरमौर तक बरसात का कहर बरप रहा है।प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाएं अपना जलवा दिखाती रहती है तो कभी बाढ का रौद्र रुप जिंदगियां लीलता है।कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं को रोक तो नहीं सकते परन्तु अपने विवेक व ज्ञान से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं।देश के हर राज्य में बरसात का कहर बरप रहा है। प्रतिवर्ष लाखों लोग आपदा का दंश झेल रहे हैं।हादसों में लोग अपंग हो रहे हैं बच्चे अनाथ होते जा रहे है।प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करनी होगी तभी इन हादसों पर रोक लग सकती है। अगर अब भी प्रकृति से खिलवाड़ बंद नहीं किया तो मानव को ऐसी सजाएं मिलती रहेगी। आपदाओं से सबक सीखना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। हर त्रासदी के बाद बचाव पर चर्चा होती है लेकिन ऐसी त्रासदियां रुकती नहीं हैं। प्रकृति के इस विनाशकारी विभीषिका से बहुत मानवीय तबाही हो रही हैं।परिवार के परिवार उजड़ गए हैं। देश के हर गांव व शहर में बरसात का कहर बरपता जा रहा है।

प्रकृति ने मानव को समय समय पर आगाह किया लेकिन आधुनिक मानव मनमानी कर रहा है ओर असमय ही काल के गाल में समाता जा रहा है। मानव को इन त्रासदियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए।सर्तकता बरतनी चाहिए कुदरत से छेड़छाड़ पूर्ण रुप से बंद करनी होगी तभी इन हादसों पर रोक लग सकती है।समय अभी संभलने का है।

नेपाल में भ्रष्टाचार व परिवारवाद के खिलाफ़ युवाओं क़े जबरदस्त आक्रोश को दुनियाँ के हर देश क़ो संज्ञान में लेना ज़रूरी

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

नेपाल में पिछ्ले कुछ दिनों में घटित राजनीतिक घटनाक्रम ने पूरे दक्षिण एशिया को हिला दियाहै।भ्रष्टाचार और परिवारवाद से त्रस्त जनता, खासकर युवाओं के जबरदस्त आक्रोश ने मात्र 36 घंटे में सत्ता की गद्दी हिला दी। पाँच पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों ने स्थिति को और अधिक उग्र बना दिया। सत्ता पलट की इस तेज़ी ने यह संकेत दिया है कि नेपाल की जनता अब किसी भी कीमत पर अपारदर्शी शासन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार आम लोग और युवा सड़कों पर उतरे, उसने यह साफ कर दिया कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब वह जनता के विश्वास पर आधारित हो।नेपाल की कुल जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत यानी 62 लाख लोग युवा हैं, और यही वर्ग देश की राजनीति का भविष्य तय करने वाला है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि वैश्विक स्तर पर भी यह बात स्पष्ट है कि, किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। नेपाल के युवाओं ने इस बार भ्रष्टाचार और पारिवारिक राजनीति के खिलाफ अपनी ताकत दिखाकर पूरे विश्व को एक सशक्त संदेश दिया है कि अब युवा पीढ़ी नेपो बेबीस यानी नेताओं के बच्चों और वंशवाद की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। युवाओं की इस ऊर्जा ने नेपाल की राजनीति को हिला कर रख दिया है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जनरेशन-ज़ेड (गेन ज़ेड) अब नेपाल का नया इतिहास लिखने जा रही है?

साथियों बात अगर हम नेपाल में हालात इस कदर हद तक बिगड़ बिगड़ने की करें तो, तीनों बड़ी पार्टियों,नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादी सेंटर,के नेताओं के घरों मेंघुसकर लोगों ने मारपीट की, घरों को आग के हवाले कर दिया और वित्तमंत्री को सड़कों पर घसीटा गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आगजनी के दौरान उनकी पत्नी की मौत हुई तो उधर जनाक्रोश को और अधिक भड़का दिया। यह दृश्य केवल राजनीतिक विद्रोह का नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ पूर्ण असंतोष का प्रतीक है। युवाओं का यह क्रोध इस बात का संकेत है कि अब पारंपरिक राजनीति को बदलने का समय आ चुका है।

साथियों बात अगर हम नेपाल की स्थिति की तुलना श्रीलंका और बांग्लादेश से करने की करें तो,जहाँ हाल के वर्षों में आर्थिक संकट और राजनीतिकअस्थिरता ने जनता को सड़कों पर ला दिया था। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन तक जनता का कब्जा, बांग्लादेश में चुनावी धांधली के खिलाफ आंदोलन और म्यांमार में सैन्य तख्तापलट ने दक्षिण एशिया की राजनीति को लगातार अस्थिर बना रखा है। अब नेपाल भी उसी राह पर चलते हुए सत्ता पलट की कगार पर पहुंच गया है। इसका सीधा संकेत है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से जूझ रहे समाजों में युवा अब चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे। साथियों बात अगर हम नेपाल क़े इस पूरे घटनाक्रम में सोशल मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होने की करें तो, नेपाल की लगभग 87 प्रतिशत आबादी मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करती है, जबकि 62 प्रतिशत लोग सक्रिय रूप से फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर और यूट्यूब पर भी युवा लगातार अपने विचार साझा कर रहे हैं। नेताओं के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया पर अपने आलीशान जीवन और लग्ज़री छुट्टियों की तस्वीरें पोस्ट करना आग में घी का काम साबित हुआ। जब देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रही हो और नेता तथा उनके परिवार ऐशो-आराम की तस्वीरें साझा करें, तो यह जनता के लिए असहनीय हो जाता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया ने जनाक्रोश को संगठित आंदोलन में बदल दिया।

साथियों बात अगर हम भारत के पड़ोस में यहराजनीतिक उथल- पुथल चिंता का विषय होने की करें तो,नेपाल बांग्लादेश,श्रीलंका म्यांमार और पाकिस्तान सभी वर्तमान में या तो राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं या सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। म्यांमार में सेना का शासन है, पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच टकराव है, श्रीलंका अब भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और बांग्लादेश में युवाओं के विद्रोह ने लोकतंत्र को झकझोर दिया है।इन सबके बीच नेपाल का यह आंदोलन दक्षिण एशिया में एक नई लहर पैदा कर सकता है।इतिहास की दृष्टि से देखें तो श्रीलंका,पाकिस्तान और म्यांमार कभी अखंड भारत का हिस्सा रहे थे। आज वे दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और सभी देशों में एक जैसी राजनीतिक चुनौतियाँ दिखाई दे रही हैं, भ्रष्टाचार बेरोजगारी, परिवारवाद, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी और युवा असंतोष। यही वजह है कि नेपाल की घटनाएँ केवल एक देश की समस्या नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति के लिए चेतावनी हैं। साथियों बात अगर हम नेपाल के घटनाक्रम नेपाल में सत्ता पलट का भारत पर सीधा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होने की करें तो,भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक संबंध हैं। दोनों देशों की खुली सीमा, व्यापार, पानी और ऊर्जा परियोजनाएँ भारत को नेपाल के साथ मजबूती से जोड़ती हैं।यदि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर भारत की सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति और आर्थिक हितों पर अवश्य पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान जैसे देश नेपाल में बढ़ती अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह नेपाल की स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समर्थन दे।

साथियों बात अगर हम युवाओं के जागरूकता की करें तो नेपाल का यह विद्रोह यह भी दर्शाता है कि दक्षिण एशिया के युवाओं में अब जागरूकता का स्तर काफी बढ़ चुका है। वे केवल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। नेपो बेबीस और पारिवारिक राजनीति के खिलाफ उठी यह आवाज़ अब केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहेगी,बल्कि बांग्लादेश,श्रीलंका, पाकिस्तान और यहाँ तक कि भारत में भी राजनीतिक वंशवाद के खिलाफ नई बहस को जन्म देगी। आगे चलकर नेपाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि यह जनआंदोलन केवल सत्ता पलट तक सीमित न रह जाए, बल्कि एक स्थायी और पारदर्शी व्यवस्था में बदल सके। यदि यह आंदोलन केवल भावनाओं के आधार पर चला और संस्थागत सुधारों तक नहीं पहुँचा, तो नेपाल बार-बार उसी राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होगा जो पिछ्ले तीन दशकों से जारी है। लेकिन यदि युवा इस ऊर्जा को सही दिशा देते हैं, तो नेपाल न केवल खुद को बदल सकता है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए प्रेरणा बन सकता है।

केरल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति

एल.एस. हरदेनिया

वैसे तो केरल अनेक चीजों में अन्य राज्यों से आगे है परंतु अभी प्राप्त एक आंकड़े के अनुसार यह बताया गया है कि केरल में 1000 बच्चों की मृत्यु का आंकड़ा 1000 में से 5 है। मतलब यदि केरल में 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से सिर्फ 5 बच्चों की मृत्यु जन्म के समय होती है। यह आंकड़ा अमरीका से भी आगे है।

केरल में जैसा कि बताया गया है कि 1000 शिशुओं में से 5 शिशुओं की मृत्यु होती है जबकि यह आंकड़ा हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर 25 है। मतलब यह कि जब 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से 25 बच्चे पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

यह आंकड़ा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा किए गए सर्वे पर आधारित है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार उन्होंने फिर इस बात को दोहराया है कि यह आंकड़ा अमरीका में बच्चों की मृत्यु दर से भी आगे है। अमरीका में शिशु मृत्यु दर लगभग 5.6 है।

देश के अनेक राज्यों में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग होता है, परंतु केरल में ऐसी स्थिति नहीं है। केरल में यदि शहरों में 1000 में से 5 शिशु मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो गांवों में भी 1000 में से 5 शिशु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दोनों का मृत्यु दर का आंकड़ा बराबर है। परंतु यदि देश में देखा जाए तो 1000 में से 28 बच्चे पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें शहरों में शिशुओं की मृत्यु का आंकड़ा 19 है। केरल में शहरी और ग्रामीण बच्चों की मृत्यु के आंकड़े में कोई अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं आम लोगों को शहर में प्राप्त होती हैं वही सेवाएं गांवों में भी प्राप्त होती हैं। यदि आज केरल में 1000 में से सिर्फ 5 शिशु मरते हैं तो उसका श्रेय केरल में जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उसको जाता है।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 में केरल में यह आंकड़ा 7.42 था। 2012 में यह आंकड़ा 8.2 था और 2023 के आते-आते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अंतर नहीं रहा। यह इसलिए कि गांवों में भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उतनी ही उपलब्ध हैं जितनी शहरों में उपलब्ध हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है।

केरल की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का अनुभव मुझे भी है। मैं केरल में एक सम्मेलन के संबंध में गया था। रात के 12 बजे मेरे कान में एकाएक दर्द हुआ। मैंने, हमारे जो सम्मेलन के आयोजक थे उनसे कहा कि मुझे कान में बहुत दर्द हो रहा है यदि मेडिकल सहायता मिल जाए तो अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि चलिए। मैंने कहा कि अभी तो अस्पताल में ओपीडी (जहां बाहर के लोगों को सुविधाएँ दी जाती हैं) बंद होगी। हमारे मध्यप्रदेश में अस्पतालों में एक समय सीमा में ओपीडी सेवा प्राप्त होती है। यदि 9 बजे से ओपीडी खुलता है तो 1 बजे बंद हो जाता है। फिर उसके बाद सिर्फ एक इमरजेंसी सेवा प्राप्त होती है। आयोजक ने बताया कि केरल में ऐसा नहीं है। केरल में 24 घंटे एक-सी सुविधा प्राप्त होती है। यदि दिन के 1 बजे रोगी को जो सुविधा प्राप्त होती है वही सुविधा रात के 1 बजे भी प्राप्त होती है। मतलब अस्पताल में सेवाएं 24 घंटे प्राप्त होती हैं। ओपीडी और नॉन-ओपीडी का कोई विभाजन वहां नहीं है। मेडिकल सुविधा शहरों और गांवों में 24 घंटे प्राप्त रहती हैं। जितनी शहर में सेवाएं उपलब्ध हैं उतनी ही गांवों में भी उपलब्ध हैं। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति रात के 1 बजे भी अस्पताल पहुंचेगा तो उसे वही सुविधा मिलेगी जो हमारे मध्यप्रदेश में ओपीडी में प्राप्त होती है। यही कारण है कि केरल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है। केरल में शिशु मृत्यु दर 1000 में से 5 है यह प्रगति अमरीका से भी ज्यादा है और केरल में यह प्रयास है कि यह आंकड़ा और भी कम हो।

एक नजर

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और केबिनेट के मंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा

पथ प्रवाह, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी केबिनेट के मंत्री अलग–अलग आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहां पीड़ितों के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और दूर करने की रणनीति पर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रीगण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आपदा से हुए नुकसान का जनपदों में जाकर गहनता से समीक्षा करेंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी करेंगे। इस समीक्षा का उद्देश्य राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की बारीकी से निगरानी करना और समस्त प्रभावित परिसंपत्तियों के नुकसान का व्यापक स्तर पर आकलन करना है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आपदा प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलकर समन्वित प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करना तथा पुनर्वास कार्यों को शीघ्र पूरा करना प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान की व्यापक समीक्षा की जाएगी ताकि आगामी रणनीतियाँ और नीतिगत निर्णय समयानुसार और प्रभावी ढंग से लिए जा सकें।

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को शांतिकुंज जन्मशताब्दी महोत्सव–2026 का आमंत्रण

हरिद्वार। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रतिनिधि युवा आइकॉन डॉ. चिन्मय पंड्या ने माननीय केन्द्रीय गृहमं=ी अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान अखिल विश्व गायत्री परिवार के रचनात्मक, सृजनात्मक वैश्विक प्रयासों पर विशिष्ट चर्चा हुई। युवा आइकॉन डॉ- पंड्या ने अमित शाह को जन्मशताब्दी महोत्सव 2026 का विशेष आमं=ण प्रदान किया। इस अवसर पर श्री शाह ने अखिल विश्व गाय=ी परिवार एवं गाय=ी मं= से अपने दशकों पुराने सम्बन्धों का स्मरण किया। गाय=ी परिवार द्वारा सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक प्रसार हेतु किए जा रहे विविध प्रयासों की श्री शाह ने हृदय से सराहना की। अखिल विश्व गाय=ी परिवार की संस्थापिका परम वंदनीया माताजी भगवती देवी शर्मा जी एवं अखंड दीपक की पावन जन्म शताब्दी वर्ष द्ध2026ऋ के अंतर्गत आयोजित हो रहे आयोजनों के संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा हुई। केन्द्रीय गृहमं=ी अमित शाह जी ने इस ऐतिहासिक आयोजन के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ व्यक्त कीं तथा इसे समाज एवं राष्ट्र के लिए एक प्रेरणास्रोत बताया। इसके साथ ही डॉ- पंड्या ने मं=ी जी को आगामी 16 सितंबर को देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन की जानकारी भी दी। इस सम्मेलन में देश-विदेश के अनेक ख्यातिप्राप्त एआई विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता सहभागिता करेंगे।

जिला योजना सहित बीस सूत्रीय कार्यक्रमों की सीडीओ ने की विभागवार समीक्षा

नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 22 किलोमीटर दूर विकास भवन सभागार भीमताल में मुख्य विकास अधिकारी अनामिका ने जिला योजना, राज्य एवं केंद्र पोषित योजनाओं के साथ ही बीस सूत्रीय कार्यक्रमों की विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों को प्राप्त धनराशि को समय से व्यय करते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति करें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मानसून काल अब खत्म होने जा रहा है इस हेतु सभी कार्यदाई संस्था निर्माण कार्यां के टेंडरिंग की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारंभ करते हुए इसी मांह स्थल में कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आगामी दिसंबर माह तक निर्माण कार्यों को कराए जाने हेतु मौसम अनुकूल रहता है इस हेतु सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि कार्य इसी मांह प्रारंभ हो जाय ताकि दिसंबर माह तक पूर्ण हो जाय। मुख्य विकास अधिकारी अनामिका ने कहा कि अधिकारी क्षेत्र में जाकर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करना सुनिश्चित कर लें, ताकि कार्यों में गुणवत्ता बनी रहे। बीस सूत्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को ए श्रेणी लाने के निर्देश सीडीओ द्वारा दिए गए। जनपद में बीस सूत्रीय कार्यक्रम में कुल 42 मद हैं वर्तमान में ए श्रेणी में 19, बी श्रेणी में 11, सी श्रेणी में 4 एवं डी श्रेणी में 8 विभाग हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने वर्तमान में डी श्रेणी वाले विभागों, जल जीवन मिशन, बायोगैस, स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पारिवारिक शौचालय, सिंचन क्षमता सृजन से संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वह प्रगति बढ़ाते हुए ए श्रेणी लाएं।

संगठन सृजन अभियान से कांग्रेस में होगा नई ऊर्जा का संचार : नवीन जोशी

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व पछ्वादून जिले के राज्य की ओर से प्रभारी नवीन जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन अभियान के तहत परवादून और पछ्वादून क्षेत्र में मजबूत संगठन और सक्रिय कार्यकर्ताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। जोशी ने बताया कि अब तक दोनों विधानसभाओं के सभी ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी राय ली जा चुकी है। उनका कहना है कि यह अभियान कार्यकर्ताओं की राय, अनुभव और सुझावों के आधार पर पार्टी को जमीनी स्तर तक मजबूत करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि 12 सितम्बर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है और परवादून क्षेत्र के लिए प्रातः साढे नौ बजे से 11 बजे तक और पछ्वादून क्षेत्र के लिए समयरू प्रातः 11 बजे से दोपहर डेए बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से उत्तराखण्ड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की शिष्टाचार भेंट

प्राकृतिक रूप से बने ग्लेशियरों और बड़े तालाबों के अध्ययन का किया अनुरोध

देहरादून/दिल्ली। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोकनिर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम, मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट कर मौसम विभाग एवं पृथ्वी विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिकों को पर्वतीय क्षेत्रों में संवेदनशील और ऊँचाई वाले स्थानों पर प्राकृतिक रूप से बने ग्लेशियरों और बड़े तालाबों का अध्ययन करवाने का अनुरोध किया है ताकि आने वाले समय में इनसे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। प्रदेश के पर्यटन, धार्मस्व, संस्कृति, लोकनिर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम, मंत्री सतपाल महाराज ने गुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली स्थित मंत्रलय भवन में शिष्टाचार भेंट कर बातचीत के दौरान उनसे कहा कि हमारे देश के विभिन्न पहाडी व संवेदनशील क्षेत्रों में प्रायः प्रकृतिक आपदायें जैसे भूस्खलन, बादल फटना व बाढ़ जैसी कठिनाईयां आती रहती हैं। इन भीषण घटनाओं से आम जनमानस को भारी

नुकसान पहुँचता है तथा बेकसूर प्राणियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। हाल ही में उत्तराखण्ड के जनपद उत्तरकाशी, पौड़ी और चमोली एवं हिमांचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर अचानक बादल फटने की घटना से लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और लोगों को प्राण रक्षा करने तक का अवसर नहीं मिल पाया। इसलिए यदि समय रहते हमें इन आपदाओं की सटीक व त्वरित जानकारी उपलब्ध होती तो इस नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि हालांकि हमारे देश के पास उन्नत उपग्रह तकनीक और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली उपलब्धा है जिनकी मदद से अत्यधिाक वर्षा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के आने की पूर्व सूचना दी जा सकती है किन्तु इस तकनीक को और सुदृढ और सटीक बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है। मौसम विभाग एवं पृथ्वी विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिकों को पर्वतीय क्षेत्रों में संवेदनशील और ऊँचाई वाले स्थानों पर प्राकृतिक रूप से बने ग्लेशियरों और बड़े तालाबों का अध्ययन करने की सशक्त आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में इनसे होने वाले नुकसान से बचा जा सके। श्री महाराज ने कहा कि उपग्रह आधाारित मॉनिटरिंग सिस्टम को सृदृढ किये जाने, बादल फटने व अन्य आपदाओं की सटीक जानकारी तुरंत सम्बन्धिात राज्यों और स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाये जाने तथा मोबाइल नेटवर्क, रेडियो, टीवी तथा अन्य संचार माधयमों से आम जनता तक चेतावनी संदेश पहुँचाये जाने की तकनीकी पर भी त्वरित कार्य करवाये जाने की नितान्त आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस घोर संकट से निपटा जा सके। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री यादव से अनुरोध करते हुए कहा कि मानवीय मूल्यों से जुड़े इस मुद्दे पर विशेष धयान देते हुए सम्बन्धिात विभाग को यथाशीघ्र त्वरित एवं सकारात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिए जायें।

उत्तराखण्ड आपदा: कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से मांगा 20 हजार करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज

एडीएम के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पीएम को किया ज्ञापन प्रेषित

देहरादून। पिछले महीनों में उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में आई भयंकर आपदा से प्रभावित लोगों को राहत मुआवजा देने, प्रभावितों के पुनर्वास व आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए बीस हजार करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने आज उत्तराखंड पहुंचे हैं अपर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी व पिथौरागढ़ की आपदाओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि प्रदेश में आई भयंकर आपदाओं के प्रभावितों को राहत मुआवजा पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों के लिए बीस हजार करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने की मांग की। इस अवसर पर उन्होंने पर्यटन और छोटे उद्योगों के लिए पैकेज की मांग की गई और राज्य की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को देखते हुए पर्यटन, तीर्थाटन, होटल व्यवसाय और छोटे उद्योग-व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दिया जाए और आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ताकि त्वरित और व्यापक राहत व पुनर्वास कार्य शुरू किए जा सकें। ज्ञापन में आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कम से कम दस दस लाख की तात्कालिक सहायता दी जाए और मकानों और संपत्तियों का आंकलन व मुआवजा दिया जाए तथा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के विस्थापन के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाए तथा प्रभावित परिवारों को टिहरी बांध विस्थापितों की तर्ज पर सुरक्षित स्थलों पर एकमुश्त विस्थापित किया जाए।

विभिन्न विभागों के वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के युवाओं के हित में एकीकृत भर्ती की व्यवस्था बनाने के दिए थे निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य के विभिन्न विभागों के वर्दीधारी उपनिरीक्षक एवं सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती में एकरूपता लाने के लिए बनाई गई एकीकृत भर्ती नियमावलियां लागू कर दी गई हैं। राज्य में विभिन्न विभागों के समूह 'ग' के वर्दीधारी उप निरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया को विहित करने के उद्देश्य से 'उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025' और वर्दीधारी सिपाही के पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया को विहित करने हेतु 'उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025' बनाए जाने के संबंध में अधिसूचनाएं शासन के गुरूवार को जारी की गई। 'उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025' गृह विभाग के अधीन वेतन लेवल-7 में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिसध् अभिसूचना), प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक (पी.ए.सी./आई.आर.बी.), अग्नि शमन द्वितीय अधिकारी के पदों और उप कारापाल (वेतन लेवल-6) के साथ ही वेतन लेवल-5 में होमगार्ड विभाग के प्लाटून कमांडर, वन विभाग के वन दरोगा, आबकारी विभाग के आबकारी उप निरीक्षक तथा युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में लागू होगी। शासन द्वारा जारी 'उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली-2025' के अंतर्गत गृह विभाग के आरक्षी पुलिस, आरक्षी पी.ए.सी., आरक्षी आई.आर.बी., अग्निशामक एवं बंदी रक्षक, वन विभाग के वन आरक्षी, आबकारी विभाग के आबकारी सिपाही, परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही तथा सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिवालयध् विधान भवन रक्षक के वेतन लेवल-3 के पदों को शामिल किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य के युवाओं के हितों व सुविधा का ध्यान रखते हुए विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षक एवं सिपाही के पदों पर एकीकृत भर्ती की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। ÷उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप वर्दीधारी पदों हेतु तैयार की गई नई नियमावलियां युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती के अवसर प्रदान करने के साथ ही राज्य की सुरक्षा और सेवा व्यवस्था को भी और अधिक सशक्त बनाएगी।

पुलिस का कारनामा: रिपोर्ट लिखाने गए पीड़ित के खिलाफ ही मामला दर्ज कर जेल भेजा

देहरादून। भीम आर्मी एकता मिशन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल कुमार आजाद ने कहा है कि रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि में शिक्षक विनोद कुमार के साथ जातिसूचक गाली गलौच व मारपीट की गई परंतु दोषियों के खिलाफ जब पीड़ित शिक्षक तहरीर लेकर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे तो उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया जो बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी एकता मिशन संगठन की राज्य सरकार से मांग है कि एक शिक्षक के साथ मारपीट करने वाले नामजद विक्की, आनंद सजवाण, हिमांशु भट्ट, अनूप रावल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आरोपियों के शीघ्र गिरफ्तार की जाए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच की जाए जिसमें पुलिस की भूमिका की भी जांच शामिल हो। उन्होंने कहा कि विनोद कुमार के विरुद्ध दर्ज एफआईआर की भी जांच की जाए ताकि सत्य सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर दोषियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया और हमारी मांगो को अगर पूरा नहीं किया गया तो भीम आर्मी एकता मिशन संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

बीएस नेगी महिला पॉलीटेक्निक में जागरूकता शिविर का आयोजन

देहरादून। जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून प्रेम सिंह खिमाल के निर्देश के अनुसार आज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून सीमा डुँगराकोटी ने बीएस नेगी महिला पॉलीटेक्निक, कौलागढ़ रोड़ में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर छात्राओं को साइबर अपराध व कानूनों के प्रति जागरूक करने का काम किया। इस अवसर पर शिविर में सचिव सीमा डुँगराकोटी ने साइबर अपराध, कमर्शियल कोर्ट, अनैतिक तस्करी, पोश एक्ट, नालसा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर तथा अन्य कानूनों के संबंध में जानकारी दी गई तथा सभी को सचेत भी किया गया कि कभी भी किसी दुर्व्यवहार से किसी कानून का गलत इस्तेमाल न करें। इसके साथ ही छात्राओं को बताया कि जब वह अपना कोर्स पूर्ण करके नौकरी में जाएंगे तो यह जानकारी लाभकारी रहेगी क्योंकि पोश एक्ट कार्यस्थल में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार पर महिलाओं का एक सहयोगी अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी भी उत्पीड़न या दुर्व्यवहार पर कार्यस्थल में बनी आंतरिक कमेटी को सूचित किया जाता है, जिसके उपरांत कमेटी द्वारा कार्यवाही कर महिलाओं को सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

देवभूमि का दर्द देखकर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहत बचाव टीमों के प्रयास को सराहा

नवीन चौहान

देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। धराली से लेकर थराली और कुमाऊं के कई इलाके आपदा से प्रभावित हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आपदा स्थलों का निरीक्षण करने देवभूमि पहुंचे।

जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान करीब चार बजे उतरा। उत्तराखंड के राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (से.नि.) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगुवाई करते हुए उनका स्वागत अभिनंदन किया।

लेकिन उत्तराखंड में मौसम प्रतिकूल होने के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जुट गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह (से.नि.), मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, प्रदेश के सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने धराली, थराली सहित विभिन्न इलाकों में चल रहे राहत अभियानों की जानकारी ली और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा राज्य सरकार की टीमों के प्रयासों की सराहना की।

बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावितों से सीधे संवाद किया। पीड़ितों से मिलकर उन्होंने उनका हाथ थामा, ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उनके संवेदनशील व्यवहार ने आपदा झेल रहे लोगों के आंसू पोंछे और उन्हें नई हिम्मत दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में आपदा से हुई क्षति और बचाव कार्यों का विस्तृत ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि सड़कों, पुलों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बहाली युद्धस्तर पर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के त्वरित सहयोग से राहत समय पर प्रभावितों तक पहुंच पाई है।

बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद अजय भट्ट, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, माला राज्य लक्ष्मी शाह, नरेश बंसल, कल्पना सैनी, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड आपदा से हुए नुकसान की भरपाई हेतु राहत पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहां आकर पीड़ितों का दुख-दर्द साझा किया है। यह उनकी आत्मीयता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। राज्य सरकार पूरी क्षमता से पुनर्वास कार्यों में जुटी है और हमें केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग मिल रहा है।

पशुपालकों की आस बनी 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कॉल कर लिया जायजा, जिले में 23 हजार से अधिक पशुओं का हुआ उपचार

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

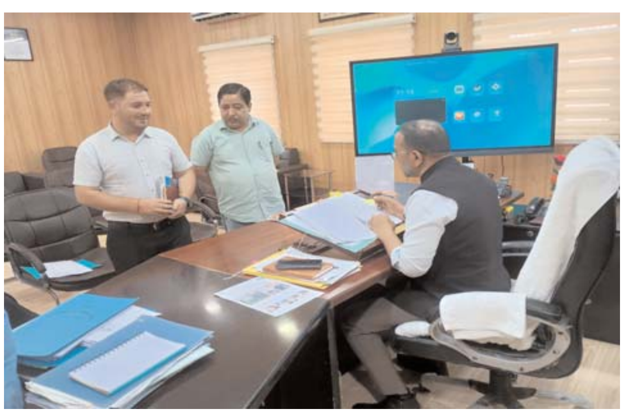

उत्तरकाशी। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट (एम.वी.यू.) उत्तरकाशी जिले के पशुपालकों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए न तो लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है और न ही महंगे इलाज का खर्च उठाना पड़ रहा है। मात्र एक फोन कॉल पर पशु चिकित्सकों की टीम उनके द्वार पर पहुंच रही है और निःशुल्क उपचार उपलब्ध करा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह सेवा किसी वरदान से कम नहीं है। गुरुवार को जिला प्रभारी नीला सिंह ने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से भेंट कर जिले में चल रही 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट की कार्यप्रणाली की जानकारी साझा की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वयं 1962 डायल कर सेवा का प्रत्यक्ष अनुभव लिया। उन्होंने कॉल रिस्पॉन्स, टीम की तैनाती और पशु उपचार व्यवस्था की बारीकी से जांच की। जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ÷यह यूनिट ग्रामीण पशुपालकों के लिए बड़ी राहत है और इसे लगातार मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जिला प्रभारी नीला सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसौड़, नौगांव और मोरी ब्लॉकों में फिलहाल पांच मोबाइल वेटरनरी यूनिट निशुल्क संचालित की जा रही हैं। ये यूनिट गांव-गांव जाकर पशुपालकों की समस्याओं को सुनते हुए पशुओं का इलाज करती हैं। अब तक जिले में 23,230 से अधिक पशुओं का निःशुल्क उपचार इन मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से किया जा चुका है। सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि टीम द्वारा बीमारियों से बचाव और पशुपालन संबंधी जागरूकता भी ग्रामीणों में फैलाई जा रही है।

पशुपालकों ने इस सेवा को अत्यंत लाभकारी बताते हुए सरकार एवं जिला प्रशासन का आभार जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि ÷पहले छोटे-छोटे रोगों के लिए भी पशु चिकित्सालय तक पहुंचना कठिन होता था, लेकिन अब घर पर ही डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। संवाददाता ने 1962 सेवा पर कॉल कर इसकी कार्यप्रणाली की भी पुष्टि की। बताया गया कि एंबुलेंस सेवा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है, जबकि मोबाइल सेवा 24 घंटे सक्रिय रहती है। उपचार के दौरान सभी आवश्यक मेडिकल दवाइयां पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सेवा न केवल पशुपालकों को आर्थिक रूप से राहत दे रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पशुधन की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है।

नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : जिलाधिकारी प्रशांत आर्य

समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए अधिकारियों को मौके पर ही दिए निर्देश

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का दायित्व है कि प्रत्येक नागरिक की समस्या को गंभीरता से लिया जाए और उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य स्वयं अपने कार्यालय में पहुँचने वाले फरियादियों की समस्याओं की तत्काल सुनवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि समस्या को टालने या अनदेखा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी और सभी विभागीय अधिकारी जनता की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें।

हीना गांव के बुजुर्ग की पेंशन समस्या का तुरंत समाधान

शुक्रवार को भटवाड़ी तहसील के ग्राम हीना निवासी जयशाही नामक वृद्ध व्यक्ति ने कार्यालय पहुँचकर वृद्धावस्था पेंशन से जुड़ी समस्या जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाज कल्याण अधिकारी को फोन कर आवश्यक कार्रवाई करने और समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कुटेटी देवी मंदिर में 3 सप्ताह से बाधित पेयजल आपूर्ति

इसी प्रकार तिलोथ वार्ड संख्या 3 निवासी ललित मोहन नौटियाल, जो कुटेटी देवी मंदिर के पुजारी हैं, ने अवगत कराया कि मंदिर में बीते तीन सप्ताह से पेयजल आपूर्ति बाधित है। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल जल संस्थान के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मंदिर परिसर में शीघ्र पेयजल आपूर्ति बहाल की जाए।

मौके पर कई शिकायतों का निस्तारण

जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में आए अन्य नागरिकों की भी समस्याओं को सुना। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि कुछ शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक सम्पन्न

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़

कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जनपद में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों का जिला उद्योग चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया गया। जिलाधिकारी ने आवेदकों से उनके नवाचार हेतु जानकारी ली, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, मार्केटिंग हेतु स्ट्रैटजी आदि।

इस अवसर पर दो उद्यमियों–वीरेंद्र सिंह वल्दिया (महरखोला, मर्सोली भाट, सीलिंग, पिथौरागढ़) को बायो फिनायल प्लांट तथा महेश जोशी (एचौली, पिथौरागढ़) को काले भट को न्यूट्रीशन उत्पाद प्लांट स्थापित करने हेतु साक्षात्कार किया गया।

बैठक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र कविता भगत ने बताया कि मिनी औद्योगिक आस्थान बिण, पिथौरागढ़ में अवस्थापना विकास कार्य विद्युत पोल व अंडरग्राउंड केबिलों के कारण प्रभावित हो रहा है। हिल्ट्रॉन बिल्डिंग के सामने तथा प्लॉट संख्या 05 से 09 एवं अन्य प्रभावित प्लॉटों पर विद्युत अवरोधों के स्थानांतरण की आवश्यकता है।

विद्युत विभाग द्वारा पोल एवं अंडरग्राउंड केबिल हटाने तथा 35 केएलडी व 05 केएलडी एसटीपी प्लांट हेतु विद्युत संयोजन स्थापित करने के लिए ?15,49,341 की धनराशि का आकलन किया गया है।

पूर्व में आयोजित बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था कि यदि 30 प्रतिशत धनराशि सांसद निधि से उपलब्ध हो जाती है तो शेष 70 प्रतिशत व्यय विद्युत विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। इस क्रम में सांसद निधि से ?4,64,802 की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा यह धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को आहरण एवं वितरण हेतु उपलब्ध करा दी गई है।

बैठक में जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को निर्देश दिए कि जितने भी औद्योगिक अस्थान में प्लॉट है उनकी सूची तैयार पूर्ण विवरण सहित तैयार कर परियोजना निदेशक ग्राम्य को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन भी उद्यमियों द्वारा औद्योगिक अस्थान में उद्योग स्थापित किए जाने है उन्हें आगामी अक्टूबर के अंत तक स्थापित किए जाने हेतु टाइमलाइन के तहत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पत्राचार करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास आशीष पुनेठा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कविता भगत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

पं0 गोविन्द बल्लभ पंत जी के जन्म दिवस के सुअवसर पर जिला स्तरीय टेबल-टेनिस प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण के साथ सम्पन्न

फाइनल मुकाबले तनुज, देवाशीष, युवराज, गौरव एवं सिमरन ने जीते

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़

खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के सौजन्य एवं जिला प्रशासन, पिथौरागढ़ के दिशा-निर्देशन में खेल विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा जिला टेबल-टेनिस संघ संघ के सहयोग से ''भारत रत्न पं0 गोविन्द बल्लभ पंत जी के जन्म दिवस'' के सुअवसर पर दिनॉक 08 सितम्बर से 10 सितम्बर, 2025 तक सुरेन्द्र सिंह वल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम, पिथौरागढ़ में आयोजित जिला स्तरीय टेबल-टेनिस प्रतियोगिता(अण्डर-11 वर्ष बालक वर्ग, अण्डर-13 वर्ष, अण्डर-15 वर्ष, अण्डर-17 वर्ष एवं ओपन बालक-बालिका वर्ग) पुरस्कार वितरण के साथ सम्पन्न हो गयी।

प्रतियोगिता के आज खेले गये फाइनल परिणाम निम्न प्रकार रहे।

अण्डर 11 बालक वर्ग में तनुज पन्त ने प्रथम स्थान, नवनीत पांडे ने द्वितीय स्थान एवं ध्रुव अधिकारी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

अण्डर 13 बालक वर्ग में देवाशीष पांडे ने प्रथम स्थान, सार्थक जोशी द्वितीय स्थान एवं आरव अरोरा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

अण्डर 15 बालक वर्ग में युवराज लोहिया ने प्रथम स्थान, अभिनव विश्वकर्मा द्वितीय स्थान एवं आशीष कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

ओपन बालक वर्ग में गौरव काण्डपाल ने प्रथम स्थान, देवांग जोशी द्वितीय स्थान एवं ललित बसेडा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

ओपन बालिका वर्ग में सिमरन लोहिया ने प्रथम स्थान, सुमन परिहार द्वितीय स्थान एवं रितु फर्सवाण ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

प्रतियोगिता टेबुल-टेनिस प्रशिक्षक ललित मोहन जोशी की देखरेख में आयोजित की गयी, जिसमें धमेन्द्र सिंह टोलिया, प्रगति कर्नाटक, प्रियंका, प्रवीन बिष्ट एवं दीपक सिंह ने निर्णायक की भूमिका निभायी।

प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि कर्नल करम सिंह बिष्ट, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, पिथौरागढ़, विशिष्ट अतिथि श्री पी0एस0 कफलिया, उपाध्यक्ष, जिला टेबल-टेनिस संघ, पिथौरागढ़ तथा ललित पन्त, महासचिव, जिला ओलम्पिक संघ, पिथौरागढ़ थे। अतिथियों ने फाइनल में पहुँचे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मुकाबलों की शुरूआत करायी तथा सभी खिलाड़ियों को भारत रत्न पं0 गोविन्द बल्लभ पंत जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए प्रेरणा लेने को कहा।

फाइनल मुकाबले समाप्ति के उपरान्त अतिथियों द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों एवं निर्णायकों को पुरस्कार/प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से 65 खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभाग का प्रदर्शन किया।

अनूप बिष्ट, जिला क्रीड़ा अधिकारी, पिथौरागढ़ ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ/पौधा भेंट कर स्वागत किया एवं स्मृति चिन्ह भेंट किया तथा सभी का आभार/धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन भूपेश बिष्ट, बैडमिन्टन प्रशिक्षक ने किया।

इस अवसर पर उप क्रीड़ाधिकारी प्रताप सिंह, राजेन्द्र सिंह जेठी, कै0 देवी चन्द्र, भूपेन्द्र सिंह चौहान, जर्नादन सिंह वल्दिया, जगत सिंह महरा, मनोज कुमार पुनेठा, निखिल महर, नीरज सिंह सौन, चन्द्र सिंह धामी, प्रशान्त सिंह भैसोड़ा, जगदीश कसन्याल, प्रकाश जंग थापा, यतीश ओझा, निखिलेश भण्डारी, विशाल नगरकोटी, जगदीश कसन्याल, मुकुल चन्द्र पाठक, मनोज रावत, भावेश भट्ट, माया कुमारी, नेहा धौनी, सरोज, पंकज भट्ट, ललित प्रसाद कापड़ी, राजेन्द्र राम, सुन्दर राम, उमेद राम, तनूजा कन्याल एवं कई खिलाड़ी उपस्थित थे।

वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान - पिथौरागढ़ पुलिस का विशेष अभियान

लोगों को साईबर क्राइम से बचने के सम्बन्ध में दी जानकारी

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़

पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव के निर्देशन में, जनपद पुलिस द्वारा ÷मित्रता, सेवा और सुरक्षा÷ के संकल्प के साथ वरिष्ठ नागरिकों की कुशलक्षेम जानने एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में उ0नि0 कमलोश जोशी, उ0नि0 हीरा सिंह डांगी, उ0नि0 मनोज जलाल द्वारा ग्राम चैंसर का भ्रमण कर बुजुर्गों से आत्मीय भेंट की गई। उनकी निजी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना गया तथा कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया।

पुलिस टीम ने बुजुर्गों को पुलिस सहायता नंबर 112 एवं मोबाइल नंबर 9411112982 की जानकारी देते हुए आश्वस्त किया कि किसी भी आपात स्थिति में वे बिना झिझक पुलिस से संपर्क करें। पुलिस सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहेगी और उनकी सुरक्षा की गारंटी बनेगी।

एक नजर

थाना जाजरदेवल पुलिस व औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा मेडीकल स्टोरों में की ताबड़तोड़ छापेमारी

मेडिकल स्टोर संचालकों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़ । एस0पी0 रेखा यादव के निर्देशन पर सी0ओ0 गोविन्द बल्लभ जोशी के पर्यवेक्षण में थाना जाजरदेवल पुलिस व औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र के मेडीकल स्टोरों में छापेमारी की गयी । इस दौरान औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल संचालकों को लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप मेडिकल संचालित करने की हिदायत दी गयी । किसी भी मेडिकल में अनियमितता पायी जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । चेकिंग अभियान में थानाध्यक्ष जाजरदेवल के नेतृत्व में पुलिस टीम, औषधि निरीक्षक पंकज पंत उपस्थित रहे ।

कोतवाली बेरीनाग पुलिस द्वारा अवैध भांग की खेती को नष्ट किया गया

जीवन सिंह बोहरा पिथौरागढ़। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित 'नशा मुक्त उत्तराखण्ड' अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़, रेखा यादव के कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एवं उत्पादन के विरुद्ध सतत रूप से प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में, आज प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बेरीनाग नरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम चौकी प्रभारी सेराघाट द्वारा ग्राम बंदरी राम मन्दिर क्षेत्र में की जा रही लगभग 02 नाली में अवैध भांग की खेती को नष्ट किया गया। इस अवसर पर पुलिस टीम द्वारा द्यक्षेत्रीय नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया तथा नशा मुक्त समाज की दिशा में सहयोग करने का आह्वान भी किया गया। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा, तथा इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगी।

दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने की क्षमता रखता है भारतीय वाहन उद्योग – गडकरी

नयी दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय वाहन उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है और इसमें दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने की क्षमता है। गडकरी ने यहां घरेलू वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के वार्षिक अधिवेशन में कहा कि कुछ साल पहले भारतीय वाहन उद्योग दुनिया में सातवें स्थान पर था, आज हम जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गये हैं। उन्होंने कहा, ÷मेरा विश्वास है आप सब लोगों की क्षमता पर। आप सब लोग यदि मिलकर काम करेंगे तो हम वाहन सेक्टर में दुनिया में नंबर एक पर जा सकते हैं।

आत्महत्या रोकथाम दिवस पर छात्रों को किया जागरूक, जीवन अमूल्य संवाद और सहयोग से ही संभव हर समस्या का समाधान

संवाददाता ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। आत्महत्या जैसी गंभीर और संवेदनशील समस्या को रोकने तथा युवाओं को सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण अपनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग उत्तरकाशी की ओर से बुधवार को आदर्श कीर्ति इंटर कॉलेज में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है बल्कि यह परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को जीवन की चुनौतियों का डटकर और सकारात्मक सोच के साथ सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कठिन समय में परामर्श लेना, परिजनों और मित्रों के साथ अपनी समस्याएं साझा करना तथा शिक्षकों के मार्गदर्शन में रहना सबसे कारगर उपाय हैं। वक्ताओं ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य की महत्ता बताते हुए यह संदेश दिया कि जीवन अमूल्य है और हर समस्या का समाधान संवाद, सहयोग एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से संभव है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में बातचीत से समाधान निकलता है, जबकि चुप्पी और अकेलापन समस्या को और बढ़ा देता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम से मीनाक्षी बुटोला, कपिल राणा, सोनिया बिष्ट, शशिबाला पंवार मौजूद रही। विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं और छात्रों ने भी सक्रिय रूप से कार्यक्रम में भाग लिया और जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिए गए सुझावों को आत्मसात करने का संकल्प लिया।

शिवालिक नगर में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर लगे रोक

पथ प्रवाह, संवाददाता

शिवालिक नगर व्यापार मंडल ने आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग रोके जाने की पुरज़ोर मांग की है। मंडल के पदाधिकारियों ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष राजीव शर्मा को पत्र सौंपते हुए कहा कि मुख्य मार्ग (80 फीट चौड़ी सड़क) और आंतरिक सड़कों पर बने आवासीय भवनों का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बदलना स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

मंडल की प्रमुख आपत्तियाँ

शिवालिक नगर और आसपास की कॉलोनियों की तेजी से बढ़ती आबादी को देखते हुए आवासीय भवनों की ज़रूरत है, लेकिन इनका इस्तेमाल धड़ल्ले से बैंकों, शोरूम, रेस्टोरेंट, होटल और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है।

वर्तमान में लगभग 1000 से अधिक भवन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बदल चुके हैं।

हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

स्थानीय व्यापारी वर्ग का कहना है कि यदि यह स्थिति बनी रही तो छोटे व्यापारी मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होंगे।

मंडल का पक्ष

व्यापार मंडल ने कहा कि शिवालिक नगर में रहने वाले अधिकांश लोग सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक हैं। वे अपनी मूलभूत ज़रूरतों–बैंकिंग, शॉपिंग और अन्य सुविधाओं के लिए यहीं के बाज़ार पर निर्भर हैं।

यदि आवासीय क्षेत्र ही व्यावसायिक रूप में बदल जाएंगे, तो स्थानीय निवासियों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

व्यापार मंडल की अपील

व्यापार मंडल ने प्रशासन और शासन से निवेदन किया है कि शिवालिक नगर की मूलभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग रोका जाए और उचित कार्यवाही की जाए।

इस पत्र पर व्यापार मंडल पदाधिकारियों समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन जताया है।

उत्तरकाशी, पुरोला और बड़कोट न्यायालयों में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

आपसी सुलह–समझौते से निस्तारित होंगे विभिन्न प्रकार के वाद, नागरिकों से अपील लोक अदालत का लाभ उठाएं

ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह

उत्तरकाशी। जिला न्यायालय उत्तरकाशी के साथ ही सिविल जज न्यायालय पुरोला एवं बड़कोट में आगामी 13 सितंबर 2025 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरकाशी के तत्वावधान में होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार ने बताया कि लोक अदालत में लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य वादों का त्वरित निस्तारण करना और न्याय की सुलभता को आमजन तक पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक संज्ञेय/शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस से संबंधित मामले), बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, वैवाहिक वाद एवं परिवार न्यायालय के वाद, मजदूरी विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, बिजली-पानी के बिल (अशमनीय मामलों को छोड़कर), राजस्व वाद (केवल जिला न्यायालय में लंबित), अन्य दीवानी मामले जैसे किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद और विशिष्ट अनुतोष संबंधी वाद शामिल होंगे। इन सभी का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा।

सचिव सचिन कुमार ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जो भी वादकारी अपने मामले का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं, वे 12 सितंबर 2025 तक अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और अन्य संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे अधिक से अधिक लोगों को इस आयोजन के बारे में जानकारी दें और नागरिकों को इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें।

राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है, जहां न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी सहमति और सुलह के आधार पर जल्दी और सरल तरीके से निपटाया जाता है। इससे न केवल वादकारियों का समय और धन बचता है बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।

एक नजर

सुप्रीम कोर्ट ने अकोला दंगों के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन करने का दिया निर्देश

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2023 में महाराष्ट्र के अकोला में हुए दंगों के मामले की जांच के लिए गुरुवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित करते हुए कहा कि एसआईटी में हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए जाएंगे।

पीठ ने दंगों के दौरान एक हत्या मामले के चश्मदीद गवाह होने का दावा करने वाले मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ की विशेष पर अनुमति याचिका यह फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने अपना यह फैसला सुनाते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि एक बार जब कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन लेता है, तो उसे सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों (धर्म, जाति आदि पर आधारित) से ऊपर उठकर कानून के अनुसार अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।

याचिकाकर्ता का दावा है कि दंगों के दौरान उस पर भी हमला किया गया था। उन्होंने इस मामले में विशेष जांच दल के गठन की मांग करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने अपनी बात कहने के लिए उचित समय सीमा में पुलिस अधिकारियों से संपर्क नहीं किया था।

रूसी सेना में शामिल होने के प्रस्तावों के झांसे में न आएं भारतीय: विदेश मंत्रालय

नयी दिल्ली। रूस की सेना में कुछ भारतीय नागरिकों की भर्ती की मीडिया रिपोर्टों के बीच विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को आगाह किया है कि वे रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव के झांसे में ना आए क्योंकि इसमें कई जोखिम हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती से संबंधित मीडिया के सवालों के जवाब में गुरुवार को कहा कि भारतीय नागरिकों को इस तरह के प्रस्ताव से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसमें खतरे हैं।

उन्होंने कहा, हमने हाल ही में रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की भर्ती की खबरें देखी हैं। सरकार ने पिछले एक साल में कई मौकों पर इस तरह की कार्रवाई में निहित जोखिमों और खतरों को रेखांकित किया है और तदनुसार भारतीय नागरिकों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने मास्को और यहां दोनों जगहों पर रूसी अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया है और अनुरोध किया है कि इस प्रथा को समाप्त कर हमारे नागरिकों को वापस भेजा जाना चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि विदेश मंत्रालय प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों के संपर्क में भी हैं। जायसवाल ने कहा, हम एक बार फिर सभी भारतीय नागरिकों से रूसी सेना में शामिल होने के किसी भी प्रस्ताव से दूर रहने का आग्रह करते हैं क्योंकि यह ख़तरों से भरा है। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्ष से भी अधिक समय से यूक्रेन के साथ संघर्षरत रूस की सेना में समय -समय पर भारतीय नागरिकों की भर्ती की जाती रही है। रूस की सेना में भर्ती होने वाले भारतीयों के परिवारों का कहना है कि सेना में भर्ती के बाद उन्हें वापस नहीं आने दिया जाता।

लोकतंत्र में हक के लिए आवाज उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार : आप

नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि लोकतंत्र में हक के लिए आवाज उठाना आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है।

आप में वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को कहा, ÷बहुत दुःख की बात है जम्मू-कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला पुलिस द्वारा मुझे हाउस अरेस्ट किए जाने की ख़बर पाकर मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट में आये उन्हें मिलने नहीं दिया गया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? उन्होंने कहा, तानाशाही चरम पर है मैं इस वक़्त श्रीनगर में हूँ। लोकतंत्र में हक के लिए आवाज उठाना आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। आज आप विधायक मेहराज मलिक की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में प्रेस कांफ्रेंस और धरना था लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी बना दिया गया है। मुझे इमरान हुसैन और साथियों को गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। उल्लेखनीय है कि सांसद संजय सिंह ने कल कहा था कि डोडा विधायक मेहराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाना गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। यह कही न कहीं केंद्र सरकार की जन विरोधी मानसिकता है। श्री मलिक जनता के लिए अस्पताल मांग रहे थे और सरकार ने उनको पीएसए दे दिया।

स्वामी/प्रकाशक **वीरेन्द्र सिंह** ने मुद्रक **प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)** से मुद्रित कराकर, **मुख्य कार्यालय: 41, शांतिपुरम, जगजीपुर, कनखल, हरिद्वार पिन–249408 (उत्तराखण्ड)** से प्रकाशित किया। **वीरेन्द्र सिंह** (सम्पादक) 9411111733, **सुरेन्द्र पाल सिंह** (ब्यूरो चीफ, उत्तरकाशी) 7376757899 वेबसाई– www.pathpravah.com